UNOFFICIAL TRANSLATION

स्टॉकहोम घोषणा

समकालीन विश्व के नीति-निर्माण के सिद्धांतों पर सहमति

आज के अर्थशास्त्र के नीति-निर्माताओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर चर्चा के लिए स्वीडन के साल्त्स्जोबादेन में 16-17 सितंबर, 2016 को दो दिवसीय बैठक में तेरह अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया, जिनमें विश्व बैंक के चार पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री थे। बैठक का आयोजन स्वीडन के अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरण (स्वीडिश इंटरनेशनल डिवेलपमेंट एजेंसी) तथा विश्व बैंक ने किया। इन अर्थशास्त्रियों में सबीना अलकिरे (ऑक्सफर्ड), प्रणव वर्धन (बर्कले), कौशिक बसु (न्यू यॉर्क), हारून भोरात (केप टाउन), अश्विनी देशपांडे (नई दिल्ली), रवि कनवुर (इथाका), जस्टिन यिफू लिन (बीजिंग), कल्ले मोइने (ओस्लो), ज्यां फिलिप प्लेटो (नमूर), जैमी सावेद्रा (लिमा), जोसेफ स्तिगलिज (न्यू यॉर्क), और फिन टार्प (हेलसिंकी व कोपेनहेगेन) शामिल थे। बैठक के अंत में अर्थशास्त्रियों के इस दल ने आपस में हुई सहमति की एक घोषणा - 'स्टॉकहोम घोषणा' - जारी करने का निर्णय किया। घोषणा इस प्रकार है।

1. विकास की चुनौती

आज का विश्व संकट काल के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक ताकतें जहां एक ओर संभावनाओं का मार्ग प्रस्तुत करती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके चलते और संकट के बादल भी मंडराते रहते हैं। तकनीकी में अभूतपूर्व प्रगति के कारण जीवन के स्तर में सुधार की संभावना तो बढ़ी है, किंतु विस्थापित श्रम और युवाओं की बेरोजागरी का संकट बरकरार है। व्यापार के विस्तार और वैश्विक निवेश के चलते वृद्धि की गति में तेजी आई है और निम्न आय के विभिन्न देश विकास के दौर में कदम बढ़ाते हुए मध्य आय के देश का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। वहीं, इन देशों में कई समुदाय पीछे छूट गए हैं। यह बात विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी लागू होती है, जहां कई समुदायों पर वैश्वीकरण की ताकतों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यही नहीं, ऐसे कई देशों में जीवन के स्तर में वस्तुतः गिरावट आई है जो संघर्ष और युद्ध से ग्रस्त हैं। देशों के भीतर बढ़ती असमानताएं सामाजिक संसक्ति और आर्थिक प्रगति को जोखिम में डालती हैं। पर्यावरण में आए क्षणन और जलवायु परिवर्तन के चलते विश्व संकट में है, और बढ़ते खतरों के निवारण की वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की राह देख रहा है। तेज रफ्तार शहरीकरण उत्पादकता के लाभों की संभावना तो जगाता है, किंतु इससे शहरों में झुग्गियों, गरीबी और संघर्ष की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।

इनमें से कोई भी कारक उस असाधारण प्रगति को कम नहीं करता, जो बढ़ती आयों में और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के सुधार में आई है। हम इन उपलब्धियों की सराहना करते हैं, और हमें भविष्य में नीति निर्माताओं के समक्ष आने वाली निश्चित चुनौतियों दिखाई देती हैं। इन चुनौतियों का एक सफल उत्तर विकास के लिए वैश्विक ताकतों का उपयोग करने संकट की बजाय संभावना के मार्ग पर चलने में निहित है। इन नीतियों को अमल में लाने के लिए विकास नीति के लक्ष्यों की एक स्पष्ट सोच, और अतीत की सफलताओं व गलतियों तथा आर्थिक सिद्धांत और लंबे समय से संचित आंकड़ा विश्लेषण से सीख लेने की

जरूरत है।

UNOFFICIAL TRANSLATION

यह अब स्पष्ट है कि अपेक्षाकृत अधिक परंपरागत अर्थशास्त्र की कुछ अनुशंसाएं मान्य नहीं थीं। नीति निर्माता नीति के प्रतिदर्श मार्गदर्शकों पर भरोसा कर सकते हैं जैसे वित्तीय संतुलन पर नियंत्रण, महंगाई पर काबू हेतु मुद्रा नीति का उपयोग करना, स्थूल आर्थिक स्थिरता कायम करना, और फिर शेष काम के लिए इसे बाजार पर छोड़ देना। इसमें इस बात की कोई संभावना नहीं है कि गरीबों की जो थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है, उसमें वृद्धि होगी। वस्तुतः, हम उस तत्कालीन सलाह के अति निकट अपनी कुछ मौजूदा स्थिति के प्रति ऋणी हैं।

यह घोषणा नीति की कोई रूप-रेखा नहीं बल्कि कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो हम आशा करते हैं कि देश स्तर की नीतियां तैयार करने में सहायता के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर संवाद को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय नीतियों के अभिकल्पन में हमारी सहायता कर सकते हैं। आज के तेजी से बदलते और एक विश्व का रूप लेते इस विश्व में इन सिद्धांतों की आवश्यकता और बढ़ जाती है।

2. सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अपने आप में कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं है

हम मानते हैं कि, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की नीतियां जरूरी हैं, किंतु इसे अपने आप में कोई अंतिम उद्देश्य नहीं बल्कि कतिपय सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी संसाधनों के सृजन का एक साधन होना चाहिए, जिनमें उन्नत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और उपभोग शामिल हैं। निजी सुख-समृद्धि बहुआयामी है और नीति का लक्ष्य न केवल आय बल्कि समाज में महत्वपूर्ण सभी आयामों में सुधार होना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, स्कूल पूर्व के सभी बच्चों के लिए बेहतर पोषण की व्यवस्था और हर व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य चिकित्सा की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा यह देखना जरूरी है कि ये सभी बातें पहुंच की सीमा में हों। यदि सही नीतियां नहीं अपनाई जाएं, तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का लक्ष्य स्थानीय पर्यावरण और वैश्विक जलवायु के क्षय समेत सुख-समृद्धि के इन आयामों के मूल्य पर प्राप्त हो सकता है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि केवल अपने बल पर संकटग्रस्त समुदायों के विरुद्ध जारी दमनकारी मानदंडों और भेदभाव की प्रथाओं को दूर करने का रास्ता नहीं दिखा सकती। इनके लिए सामान्य स्थिति में सुविचारित प्रयासों की जरूरत होती है।

हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि सभी अर्थव्यवथाओं (देशों) के लिए कोई एक नुस्खा सही नहीं माना जाएगा। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में फर्क होता है, जैसे इतिहासों में। इस तथ्य के फलस्वरूप अलग-अलग समाजों की अपेक्षाएं अलग-अलग होती हैं, और क्या कारगर होगा क्या नहीं यह तय करने में इसकी एक भूमिका होती है। अतीत में सभी राष्ट्रों के लिए एक एकरूप नीति संहिता (कुछ समृद्ध देशों में रचित) लागू करने की एक प्रवृत्ति थी। हालांकि नीति के कई विस्तृत सिद्धांत हैं जिन पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए, किंतु नीति की विविधता और संदर्भ-केंद्रिकता की गुंजाइश भी होनी चाएिह।

3. विकास समावेशी होना चाहिए

हम मानते हैं कि नीति को यह सुनिश्चित करने में सहायक होना चाहिए कि विकास सामाजिक और आर्थिक रूप से समावेशी हो और समाजों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए - न तो लिंग के आधार पर, न जातीयता, अथवा न ही अन्य

UNOFFICIAL TRANSLATION

सामाजिक सूचक के आधार पर। सुख-समृद्धि के विभिन्न आयामों में घोर वंचना पर विशेष ध्यान होना चाहिए, और खास तौर पर उन लोगों पर जो एक साथ कई आयामों में वंचना से ग्रस्त हों। किंतु, सर्वाधिक वंचितों पर ध्यान देना ही काफी नहीं है। अमीर और गरीब के बीच, और समाज के विशेष समुदायों के बीच, अंतर भी महत्वपूर्ण है। आय और धन की असमानता में हाल के दशकों में हुई वृद्धि और मूलभूत सेवाओं - जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा - की सुलभता के अवसरों में असमानता के स्तर को जातीयता के आधार पर समर्थन नहीं दिया जा सकता, ये कारक सामाजिक संसक्ति को क्षति पहुंचाते, और नीति पर अभिजात वर्ग की उत्तरोत्तर बढ़ती पकड़ को बढ़ावा देते हैं जो असमानता को और तीव्र कर देता है। उच्च स्तर की असमानता में गरीबों की आवाज छीन लेने की प्रवृत्ति होती है, जिससे प्रजातंत्र कमजोर होता है। महिलाओं और सदियों से भेदभाव प्रभावित समुदायों का सशक्तीकरण एक प्राथमिकता है, किंतु यह आर्थिक सक्षमता का एक ठोस आधार भी उपलब्ध कराता है। यदि राजनीति में अशांति और समाज में संघर्ष जारी रहे, तो विकास नहीं हो सकता; और यदि विकास की नीतियां समावेशी नहीं हों, तो समाज में संघर्ष पनप सकता है। बहरहाल, समावेशी विकास विकास का एकमात्र सामाजिक और आर्थिक स्वरूप है।

4. पर्यावरण का संरक्षण कोई स्वैच्छिक विषय नहीं, अनिवार्यता है

हालांकि इसे हर देश और क्षेत्र के संदर्भ में अलग-अलग ढंग से उत्प्रेरित और लागू किया जाएगा, किंतु हम मानते हैं कि विकास के नीति-निर्माण में पर्यावरण के संरक्षण को केंद्र में रखा जाना चाहिए। स्थानीय पर्यावरण के क्षणन से इसका सीधा संबंध है, जहां केवल आय में वृद्धि से सुख-समृद्धि और प्रगति का एक मिथ्या संकेतक सामने आ सकता है। इसके अतिरिक्त, संसाधनों पर होड़ और पर्यावरण से जुड़े पलायन के चलते असुरक्षा और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं जो विकास को बाधित करते हैं। विश्व स्तर पर, जलवायु परिवर्तन विश्व की जीवन-शक्ति के लिए एक दीर्घकालिक, और, समान रूप से, कई देशों में जीविकोपार्जन के विभिन्न उपायों, खेती और आवास के लिए एक अल्प-से-मध्यकालिक संकट है। इसमें विश्व स्तर पर कमी लाने के प्रयास सबसे पहले और सर्वाधिक प्राथमिकता के साथ किये जाने चाहिए, जबकि राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर अनुकूलन नीतियों के लिए सक्रिय सहभागिता और सहायता की आवश्यकता है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें समाधान के लिए मुक्त बाजार पर छोड़ा नहीं जा सकता। राज्यों के नियामक प्रयास तथा एक निश्चित परिमाण में बहु-देशीय नीति का समन्वय अपरिहार्य है।

5. बाजार, राज्य और समुदाय के संतुलन की जरूरत

इन उद्देश्यों और विश्व समुदाय के समक्ष खड़ी वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के रू-ब-रू, विकास की नीति का निर्माण बाजार, राज्य और समुदाय के बीच विवेकपूर्ण संतुलन पर होना चाहिए। यह समझ लेना जरूरी है कि निर्माता स्वयं सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके लिए संसाधनों के प्रभावकारी आर्थिक विनिधान के आश्वासन को पूरा करने हेतु विनियमन के एक प्रभावशील ढांचे की जरूरत है। वहीं, बाजार प्रभावकारिता के लक्ष्य को पूरा करते हैं, किंतु उनमें समावेशन और समानता के लक्ष्य को पूरा करने के प्रति कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। जैसा कि अब हम जानते हैं, अकाल मुक्त बाजार की सक्षमता के अनुरूप होते हैं। बीती सदी के अंतिम वर्षों के मुक्त बाजारों के प्रति यह प्रवृत्ति वित्तीय संकटों, असमानता तथा असतता के अस्थिर स्तरों समेत उन विभिन्न परिणामों को परिलक्षित करती है जिनके साथ आज विश्व चल रहा है।

UNOFFICIAL TRANSLATION

बाजार के सामर्थ्य की सीमा को स्वीकार करते हुए, हमारा मानना है कि राज्य को स्वयं सक्षमतापूर्वक कार्य करना चाहिए। ऐसे कई रास्ते हैं, जिनमें देश बाजारों से परे जा सकते हैं - ऐसी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जिनका सरकार को विभिन्न स्तरों पर और ऐसे अनेकानेक स्वरूपों में निर्वाह करना है जो नागर समाज ग्रहण कर सकता है, जैसे सहकारी संस्थाएं, परिसंघ और गैर-सरकारी संगठन। राष्ट्र राज्य को ऐसे कार्यों को हाथ में नहीं लेना चाहिए जिन्हें बाजारों अथवा समुदायों पर छोड़ना ही बेहतर हो। अकसर, ये संस्थाएं पूरक तरीकों से साथ मिलकर कार्य करती हैं। ऐसे संदर्भ मिलते हैं, जहां सर्वाधिक वंचितों के लिए स्थानीय संस्थाएं समुदाय स्तर पर अपनी गतिविधियों से बेहतर ढंग से सुख-समृद्धि के कार्य करती हैं। इसके बावजूद हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि स्थानीय सामुदायिक संस्थाओं पर प्रतिगामी ताकतों, नागर समाज के संगठनों की पकड़ है, और सामाजिक संसक्ति को बढ़ावा देने और बनाए रखने में उनकी एक अहम भूमिका होती है।

हम फिर कहते हैं कि खेल के उन नियमों के निर्धारण में और एक नियामक संगठन की स्थापना में राज्य की भूमिका अपरिहार्य है, जिनमें बाजार और समुदाय फल-फूल सकें और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। समाज की उस उच्चतर संसक्ति और विश्वास की असमानता में भी कमी आएगी, जो खेल को प्रोत्साहन देने के नियमों में सुधार लाते हैं। वहीं, वृद्धि तथा सुख-समृद्धि को उसके सभी आयामों में बढ़ावा मिलेगा। जिन क्षेत्रों में बाजार बेहतर प्रदर्शन नहीं करते, जिनमें अकाल, स्वास्थ्य और पर्यावरण मुख्य उदाहरण हैं, और जहां समावेशन की अनिवार्यताएं स्पष्ट हैं, जैसे महिलाओं का सशक्तीकरण, संकटग्रस्त समुदाय की रक्षा, और धन और आय की व्यापक असमानता का निवारण - उनमें भी राज्य की एक अनिवार्य भूमिका होती है। औद्योगिक नीति तथा कृषि एवं सेवा क्षेत्र की नीतियों को आकार देने में भी इसे एक किरदार अदा करना है। राज्य को, राज्य की पकड़ का मार्ग प्रशस्त करने वाली बढ़ती असमानता के चक्रों को अनिवार्य रूप से रोकना चाहिए, जिसके चलते समाज में, राजनीति में और अर्थव्यवस्था में असमानता मजबूत होती है।

6. वृहत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कराना

परंपरागत नीति का अधिकांश सुझाव वृहत आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता पर केंद्रित था। उच्चतर स्थायित्व वाली अर्थव्यवस्थाएं वृद्धि की बेहतर स्थिति और कल्याण के संवर्धन में ही सफल होती हैं। वृहत आर्थिक स्थिरता अर्थव्यवस्था को एक संतुलित आधार देने और आज की नीतिक गतिविधियों, खास कर वित्तीय एवं बाह्य वित्तीय स्थिरता, के अपेक्षाकृत अधिक दीर्घकालिक निहितार्थों पर ध्यान देने हेतु नीतियों के प्रबंधन को अनिवार्य बनाती है। वित्तीय संसाधनों के निर्माण के लिए देशों को चरम वृद्धि के कालों का उपयोग करना चाहिए ताकि इस आवश्यकता के पनपने पर वे इस रामबाण का उपयोग करने की स्थिति में हों। किंतु, एक ऐसा वित्तीय अनुशासन जरूरी है जो दीर्घ काल तक चले, और इस पर बल देने के लिए परंपरागत अर्थशास्त्र उचित है, नीति निर्माता बजट के संतुलन के एक अंध निर्धारण का कार्य अकसर छोड़ दिया करते थे।

यह मान लेना चाहिए कि आर्थिक प्रोत्साहन और सार्वजनिक निवेश अकसर विकासहीनता के घातों से बचने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और वे तब तक सुरक्षित रहते हैं, जब तक ऋण का सावधानीपूर्वक संचालन होता रहता है और मौद्रीकरण के स्फीतिकारी प्रभाव नियंत्रित रहते हैं। आधारभूत संरचना और हरित तकनीकी के निर्माण के लिए

UNOFFICIAL TRANSLATION

सार्वजनिक निवेश जरूरी होता है, जहां निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु लाभ दूर भविष्य में निहित होते हैं। इसके अतिरिक्त, वृहत मितव्ययी उपाय बुदबुदों के विकास को हतोत्साहित करने, संभावित अस्थिर पूंजीगत गतिविधियों को कम करने, और बाह्य ऋणों में व्यापक वृद्धि को रोकने के लिए मुद्रा नीति की सहायता कर सकते हैं।

7. वैश्विक तकनीकी एवं असमानता के प्रभाव पर ध्यान देना

नीति-निर्माण के क्षेत्र में हाल में तकनीकी में हुई प्रगतियों के साथ एक खास चुनौती समाने आई है। नई तकनीकी विश्व श्रम बाजार को जोड़ रही है, स्वयं को पुनर्स्थापित किए बिना इसने विकासशील देशों में कामगारों के लिए विश्व बाजारों और उपभोक्ताओं के लिए काम करना आसान कर दिया है। इसके फलस्वरूप कामगारों के लिए नए अवसर पनपे हैं किंतु, वहीं राष्ट्रों के भीतर असमानता तीव्र हुई है। उच्च आय वाले देशों में इसे श्रम-बनाम-श्रम समस्या के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, विकासशील देशों के कामागरों के हितों को के विकसित देशों के कामागारों के हितों के विरुद्ध रखते हुए। इसकी अनदेखी की जाती है कि यह वस्तुतः वृहत स्तर पर एक श्रम-बनाम-पूंजी समस्या है। स्व-नियंत्रण, रोबोतंत्र के आविर्भाव और श्रम बाजार के वैश्वीकरण से न केवल श्रम विस्थापित होता है बल्कि इससे कामगारों की कमाई का स्थान उच्चतर स्तर के लाभ ले लेते हैं। ये परिणाम एक चिंता हैं जिन्हें, इसे वैश्विक श्रम-बनाम-श्रम संघर्ष का रूप दिए बिना, दूर किया जाना चाहिए।

यह नीति की तीन अनिवार्यताओं को जन्म देता है। पहली, हमें मानव पूंजी में निवेश और कौशलों का विकास इस प्रकार करना चाहिए कि वे तकनीकी के पूरक हों और इस तरह तकनीकी में वृद्धि करने के साथ-साथ श्रम की आय को बढ़ावा दें। दूसरी, देशों में हमें आय हस्तांतरणों के नए उपकरणों का विकास करना है। सकल घरेलू उत्पाद में मजदूरी के अंश में गिरावट को तकनीकी में वृद्धि के किसी अपरिहार्य परिणाम के रूप में कतई नहीं देखना चाहिए। इस समानार्थकता को तोड़ने के लिए सरकारों को करों और लाभ-अंशधारिता की प्रणालियों का निर्माण करना चाहिए, और उन्हें खेल के नियम का निर्धारण करना चाहिए - जैसे प्रतिस्पर्धा कानूनों और श्रम विधान का सख्त क्रियान्वयन - जो कामगारों की मोल-तोल की शक्ति को और तीक्ष्ण करें तथा समाज में और कंपनियों के भीतर उनकी आवाज को और मुखर करें। अंतिम, यह बहु-देशीय नीति-निर्माण की एक विशेष जरूरत को जन्म देता है। यह देशों में नीति के समन्वयन को बढ़ावा देने तथा उन नीतियों को प्रोत्साहित करने का बहुपक्षीय संस्थाओं को दायित्व देता है, जो न केवल अमीर, औद्योगीकृत राष्ट्रों बल्कि उभरते देशों के हितों का भी ध्यान रखती हों, अंतरराष्ट्रीय नीति-निर्माण की प्रक्रिया में जिनकी आवाज अकसर अनसुनी रह जाती है।

8. सामाजिक मानदंड और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं

अर्थशास्त्र में अधिकांशतः यह धारणा प्रबल रही कि हमारे आर्थिक जीवन पर सामाजिक नियमों और मानसिकताओं के प्रभाव कम पड़ते हैं। किंतु शोध से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। हमारी मूल्य-मान्यताएं और संस्कृति केवल अपने में महत्वपूर्ण नहीं हैं, किसी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के ढंग पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। एक ऐसा समाज जिसमें लोगों का एक दूसरे पर विश्वास हो उस समाज से बेहतर प्रदर्शन करता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। उदाहरण के लिए, लोगों के समक्ष भिन्न क्रम में या अलग-अलग अनुपस्थित विकल्पों के साथ

UNOFFICIAL TRANSLATION

अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत किए जाने पर, समान विकल्पों के कारण लोगों की पसंद में अंतर आ सकता है। अपने कार्यक्रमों व सेवाओं के अधिक असरदार ढंग से संचालन के लिए सरकारों को इन नई अंतर्दृष्टियों और नए उपकरणों का उपयोग शुरू करना चाहिए। अपने हितों और लाभों में वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियां और निगम लंबे समय से मानव मनोवृत्ति व समाज की अभिरुचियों के अपने ज्ञान का उपयोग करते और अकसर उसका लाभ लेते रहे हैं। यदि सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावकारी ढंग से लागू और करों का संग्रह समुचित ढंग से करना चाहें, तो लोकहित में सामाजिक मानदंडों की हमारी बृहत्तर समझ को नीति-निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक मानदंड और दृष्टिकोण भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह वह क्षेत्र है, जिसमें राष्ट्रों की संदर्भ-केंद्रिकता खास तौर पर महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मानदंड और दृष्टिकोण हर समाज के इतिहास और अनुभव के परिणाम होते हैं।

9. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की वैश्विक नीतियां एवं दायित्व

वैश्विक शक्तियां देशों की सरकारों के लिए विकास नीति के खुले विकल्पों का नित्य सृजन करती हैं। वे प्रतिबंध और अवसर पेश करती हैं और बदले में अन्य देशों में अभियान चलाकर उनका भी निर्धारण किया जाता है।

उच्च आय वाले देशों में मुद्रा नीति विकासशील देशों को पूंजी के प्रवाह की संभावनाओं को प्रभावित करती है। समृद्ध देशों में वित्त विनियमन की नीतियों का, जो यद्यपि फौरी तौर पर इन देशों को प्रभावित करती हैं, अंततः उभरते और विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ता है, जैसा कि वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान व्यापक रूप से सामने आया। कर मुक्त देशों पर लागू नीतियों एवं विनियमों का सभी देशों की, और खास तौर पर निम्न आय वाले देशों की समावेशी व सतत विकास की उनकी नीतियों के वित्त पोषण हेतु राजस्व सृजन की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। किसी देश की व्यापार नीतियां अन्य देशों के लिए निर्यात की संभावनाओं पर प्रभाव डालती हैं। उच्च आय वाले देशों में पलायन नीतियों का निम्न आय देशों के नागरिकों के अपने जीवन स्तर को बेहतर करने, और धन-प्रेषण (प्रेषित धन) तथा शिक्षा हस्तांतरण के जरिए ऐसा करते हुए, उनके अपने गृह देशों के विकास में सहायता करने की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे सभी मामलों में, आज के वैश्वीकृत विश्व में हर देश का अन्य देशों पर समपार्श्विक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में, विश्व के सर्वाधिक वंचित नागरिकों के लिए विकास के अवसरों पर ध्यान रखना और उन्हें आगे बढ़ाना सभी देशों का दायित्व है।

विभिन्न देशों के बीच अनुबंध और उनमें कार्यरत संस्थाएं हमारे समय की कुछ भारी समस्याओं के निपटान में निर्णायक महत्व रखते हैं। किंतु, इन अनुबंधों और संस्थानों की स्थापना व रखरखाव अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता एक अच्छी शुरुआत का परिचायक है, किंतु विश्व को उत्सर्जन के संकल्पों के सभी देशों में अनुपालन, और जलवायु परिवर्तन - पलायन व अनुकूलन दोनों - से जुड़े निम्न आय देशों के प्रयासों को उच्च आय देशों की वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा है। हाल के वर्षों में परंपरागत स्रोत तथा भारी संख्या में नए द्विपक्षीय व बहुपक्षीय विकास के संस्थान सामने आए हैं, किंतु कहने की आवश्यकता नहीं कि औपचारिक विकास सहायता, जिस पर दशकों पूर्व विश्व समुदाय की सहमति बनी थी, के 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति का लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। यह सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है कि सहायता विकासशील

UNOFFICIAL TRANSLATION

देशों को, और उनके भीतर हाशिए के समुदायों को दी जाए, और, कि विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की शासन संरचना में बेहतर स्थान मिले, जो बदले में यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों और समझौतों में विकासशील देशों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखा जाए।

10 आगे की सोच

विकास की चुनौतियों के निपटान में यदि देश बाजार, राज्य और समुदाय के संतुलन की व्यावहारिक नीतियों का पालन करें, और वैश्विक शक्तियों के प्रतिबंधों को यदि विश्व समुदाय कम करे और जुटाए जा रहे नए अवसरों का लाभ ले, तो विश्व में हो रही तकनीकी प्रगतियों को सर्वाधिक वंचितों समेत सभी की सुख-समृद्धि की प्रगति के रूप में बदला जा सकता है। हमें एक ऐसा विश्व मिल सकता है, जिसमें सभी समृद्ध हों। अतीत की गलतियां और सफलताएं सिद्धांतों के एक विन्यास का संकेत देती हैं, जिसके गिर्द राष्ट्र और विश्व स्तर की इन नीतियों का गठन किया जा सकता है। विकास के सिद्धांतों के अनुरूप इन सिद्धांतों को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने का यही उपयुक्त समय है।